(d) whether Government propose to recover the whole money from Shri Sanjay Gandhi?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). Yes, Sir. In connection with Lok Sabha Unstarred Questions No. 68, No. 528 and No. 3444 answered on 6-4-1977, 15-6-1977 and 13-7-1977 respectively the State Governments were asked to furnish details regarding the visits of Shri Sanjay Gandhi to the States. The information collected has been laid on the Table of the House in reply to the above Questions.

(d) This is a matter for the State Governments to consider.

राजस्थान के भागों के विकास के लिए धनराशि का नियतन

4102. श्री मीठालाल पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत सरकार ने हाल में राजस्थान के कुछ भागों के विकास के लिए कुछ धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो उस धनराशि के खर्च के लिए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने 1977-78 के दौरान राज्य की आदिवासी उप-योजना के बारे में राजस्थान को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 2.60 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। 58 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार को पहले ही दे दी गई है। धनराशि आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के विकास में राज्य के प्रयास में सहायता के लिए है, जो 6 83 करोड़ रुपए होगी। यह राशि निम्नलिखित कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी :—

(1) कृषि

(2) सहकारिता

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण

(4) उद्योग

(5) सड़क तथा पुल

(6) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं।

बेतूल का विकास

4103. श्री सुभाष आहूजा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक दृष्टि से क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने अथवा कम करने के लिये सरकार का विचार नये उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में बेतूल को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी जो पिछड़ा हुआ और आदिवासी क्षेत्र है?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख). संतुलित क्षेत्रीय विकास सरकार की स्वीकृत राष्ट्रीय नीति है। सरकार ने तकनीकी आर्थिक बातों को ध्यान में रख कर पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की है साथ ही ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिये जाते हैं। मध्य प्रदेश का बेतूल जिला पहले से ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने के लिए स्वीकृत जिलों मे से है किन्तु यह निवेश पूंजी राज्य सहायता पाने का पात्र नहीं है।

Reduction in Overhead Cost by CIL

4104. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Coal India Ltd. has effected a reduction in overhead expenses to the tune of Rs. 100 crores